भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4022

उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

स्कूलों और कॉलेजों के अध्ययन पाठ्यक्रम का डिजिटलीकरण

†4022. **श्री अशोक कुमार रावत:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में मौजूदा अध्ययन पाठ्यक्रम को डिजिटल बनाने हेतु क्या पहल की गई है;

(ख) अध्ययन पाठ्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है और इस कार्य को पूरा करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) ऐसी चल रही परियोजनाओं में निधि का नियमन करने वाली प्रमुख नीतियों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं के लिए निधि के उपयोग में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में चल रही परियोजनाओं में निधि के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का भाग है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासन के अधीन हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष रूप से मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान और डिजिटल साक्षरता सहित शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया है। एनईपी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसमें शिक्षा क्षेत्र को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक समग्र, लोचशील और बहुविषयक बनाने की परिकल्पना की गई है।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के भाग के रूप में दिनांक 17 मई, 2020 को **'पीएम ई-विद्या'** नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई, जो देश भर में शिक्षा तक बहु-माध्यमीय पहुंच

को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्र का वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, साथ ही सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) भी उपलब्ध कराई जाती हैं। दीक्षा में भागीदार के रूप में, उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/स्वायत्त निकायों (एबी) ने कक्षा 1-12 के लिए मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए 3.69 लाख से अधिक सामग्री तैयार की और योगदान दिया है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 564.05 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं। हितधारकों को दीक्षा पर 300 से अधिक वर्चुअल लैब तक पहुंच प्राप्त है।

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के माध्यम से सभी 404 पाठ्यपुस्तकों को डिजिटल और सक्रिय कर दिया है, जिनमें मूलभूत चरण से शुरू होने वाली नई पाठ्यपुस्तकें और क्यूआर कोड के साथ सक्रिय पाठ्य पुस्तकें (ईटीबी) शामिल हैं। एनसीईआरटी ने बच्चों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षा 1, 2, 3 और 6 के सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद भी किया है। ये ईटीबी दीक्षा (http://diksha.gov.in), ई-पाठशाला (http://epathshala.nic.in) और एनसीईआरटी पोर्टल (https://ncert.nic.in/textbook.php) पर उपलब्ध हैं, जिससे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को आसानी से इन तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। क्यूआर कोड इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कई शिक्षण संसाधनों से जुड़े हुए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लगभग 6778 पाठ्यपुस्तकों को ईटीबी में परिवर्तित कर दिया है। एआईसीटीई द्वारा तैयार पाठ्यचर्या सामग्री और पुस्तकें ई-कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध हैं और सभी हितधारकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों में पाठ्यचर्या का डिजिटलीकरण नियमित कार्यप्रवाह निधि का हिस्सा है।

जारी परियोजनाओं में निधि के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: कर्मचारियों, विक्रेताओं और प्रतिभागियों को किए जाने वाले भुगतान (आयकर भुगतान, टीडीएस और जीएसटी जैसे कर भुगतानों के अतिरिक्त) सहित सभी भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से किए जाते हैं।

******